उत्तराखंड में आर्थिक और वित्तीय गतिविधियां*

दीपक मोहंती

'हरित क्रांति' का पथप्रदर्शित करने वाली कृषि अनुसंधान की इस बहुप्रतिष्ठित संस्था में युवक श्रोताओं से विचार साझा करने हेतु आमंत्रित करने के लिए मैं प्रोफेसर मूर्ति को धन्यवाद देता हूं। मैं, आज की इस चर्चा में राज्य की आर्थिक और वित्तीय संरचना के साथ ही भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तीय समावेशन की दिशा में उठाए गए विभिन्न कदमों की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करूंगा। उसके बाद मैं, संवृद्धि की गति को बनाए रखने के लिए कुछ नीतिगत चुनौतियों की चर्चा करूंगा। चर्चा का समापन मैं कृषि अर्थव्यवस्था पर अपने विचारों के साथ करूंगा।

मुख्यरूप से मैं, 2000 के प्रारंभ से आर्थिक गतिविधियों को ढूंढ़ने की कोशिश करूंगा क्योंकि भारत गणराज्य के 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड की स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी। देवभूमि के रूप में जाना जाने वाला यह राज्य प्रकृति प्रेमियों और साहसी खेल पसंद करने वाले लोगों के लिए सचमुच स्वर्ग है जिसे प्रकृति ने उदारतापूर्वक ग्लेशियरों, नदियों और वनों से नवाज़ा है। यह कम जनसंख्या घनत्व वाले कुछ राज्यों में से एक है जिसका देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में योगदान 1.6 प्रतिशत है और देश की कुल जनसंख्या में इसका योगदान सिर्फ 0.8 प्रतिशत है। हिमालय की तराई में स्थित उत्तराखंड के भूभाग और कृषि-जलवायु की परिस्थितियों में वृद्धि और विकास के लिए स्पष्टरूप से चुनौतियों के साथ ही अवसर भी हैं।

समष्टि आर्थिक प्रवृत्तियां

2000 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक वृद्धि में तेजी आई। ध्यान देने की बात है कि उत्तराखंड राज्य में इससे भी अधिक वृद्धि हुई है और इस प्रकार से यह भारत के सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्य के रूप में सामने आ रहा है (चार्ट 1)।

राज्य की संवृद्धि में तेजी का पता इस बात से भी चलता है कि यहां की प्रतिव्यक्ति आय में 168 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2001-02 में यहां पर प्रतिव्यक्ति आय ₹ 19,457 थी जो 2011-12 में बढ़कर ₹ 52,125 हो गई। उत्तराखंड में प्रतिव्यक्ति आय में हुई वृद्धि अखिल

चार्ट 1 : संवृद्धि की वार्षिक प्रवृत्तियां

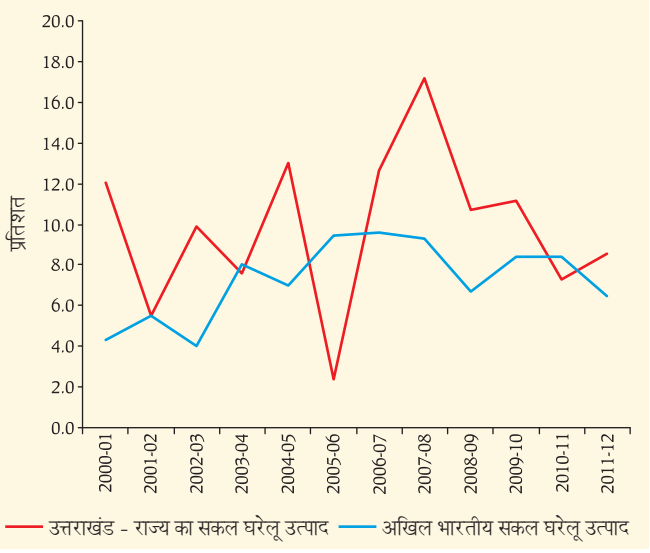

भारतीय प्रतिव्यक्ति आय की तुलना में काफी अधिक रही है। उक्त अवधि में भारत की प्रतिव्यक्ति आय ₹ 20,943 से बढ़कर ₹37,851 हो गई है। इस प्रकार से इसमें 81 प्रतिशत की वृद्धि हुई है (चार्ट 2)। इस वृद्धि के कारण 28 राज्यों में उत्तराखंड का क्रम 17वें स्थान से काफी बढ़कर 10वां हो गया है।

चार्ट 2 : प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि

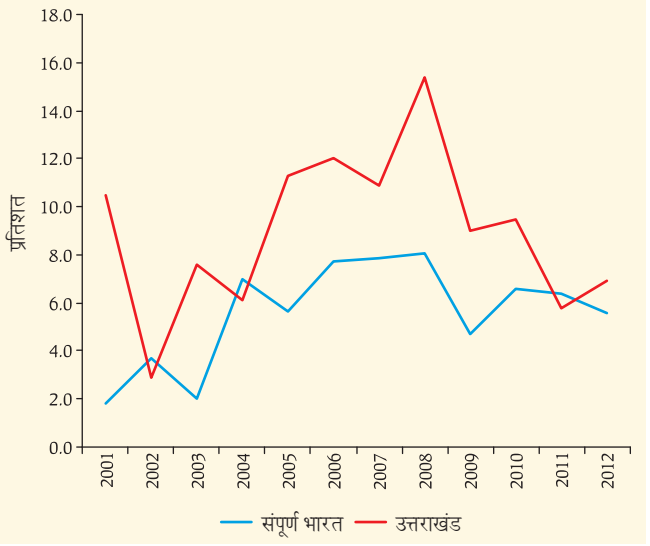

* श्री दीपक मोहंती, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जी.बी. पंत कृषि प्रौद्यागिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर में 31 अगस्त 2012 को दिया गया भाषण। इस लेख को तैयार करने में पी.के. नायक और एस. सुराज से प्राप्त सहयोग के लिए हम उनके आभारी हैं।

चार्ट 3 : वृद्धि की क्षेत्रवार प्रवृत्तियां

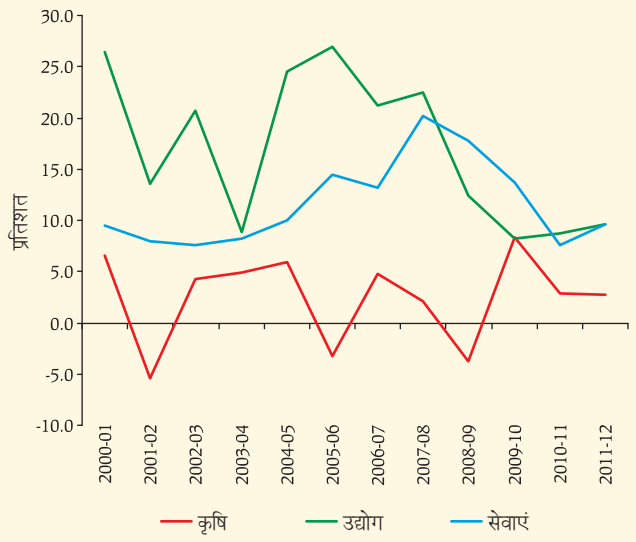

सारणी 1 : व्यापक उद्योग समूहवार रोजगार का हिस्सा

(प्रतिशत)

गतिविधि	2010-11	
	उत्तराखंड	संपूर्ण भारत
कृषि एवं वानिकी	33.5	52.2
खनन और उत्खनन	0.3	0.7
विनिर्माण	11.6	10.6
विद्युत	0.7	0.4
निर्माण	20.9	8.7
व्यापार	10.2	7.7
परिवहन एवं भंडारण	2.7	3.5
वित्तपोषण और बीमा	0.7	1
समाज सेवाएं	13.8	8.4
अन्य	5.6	6.8
सभी	100	100

स्रोत : श्रम ब्यूरो, भारत सरकार

2001-08 के दौरान शुरुआती चरण में विकास की धारा उद्योग और सेवा क्षेत्रों से प्रष्फुटित हुई। 2009-12 के बाद वाले चरण में विकास में सेवा क्षेत्र का योगदान प्रमुख रहा। हालांकि दोनों ही चरणों में कृषि का विकास निम्न और उतार-चढ़ाव वाला रहा (चार्ट 3)।

क्षेत्रवार वृद्धि में विविधता की प्रवृत्तियों को दर्शाते हुए राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग और सेवा क्षेत्र की तुलना में कृषि का योगदान घट गया (चार्ट 4)। ध्यान देने योग्य बात यह है कि भूभाग और भौगोलिक स्थितियों के चुनौतीपूर्ण होने के बावजूद राज्य में उद्योग क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

विकास की प्रवृत्तियों को और अधिक असमग्र रूप से विश्लेषित करने पर पता चलता है कि राज्य की अर्थव्यवस्था की वृद्धि में विनिर्माण, निर्माण और व्यापार तथा होटल क्षेत्रों की अग्रणी भूमिका रही (चार्ट 5)।

श्रमिक शक्ति की संरचना राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की संरचना की प्रतिकृति को दर्शाती है। रोजगार में कृषि क्षेत्र का योगदान 33 प्रतिशत रहा जो लगभग 52 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत की तुलना में काफी कम रहा। रोजगार में निर्माण, व्यापार और विनिर्माण क्षेत्र के श्रमिकों का योगदान राष्ट्रीय औसत की तुलना में अधिक रहा (सारणी 1)। हालांकि, 2010-11 में लभगग 47 प्रतिशत योगदान

चार्ट 4 : संवृद्धि की क्षेत्रवार संरचना

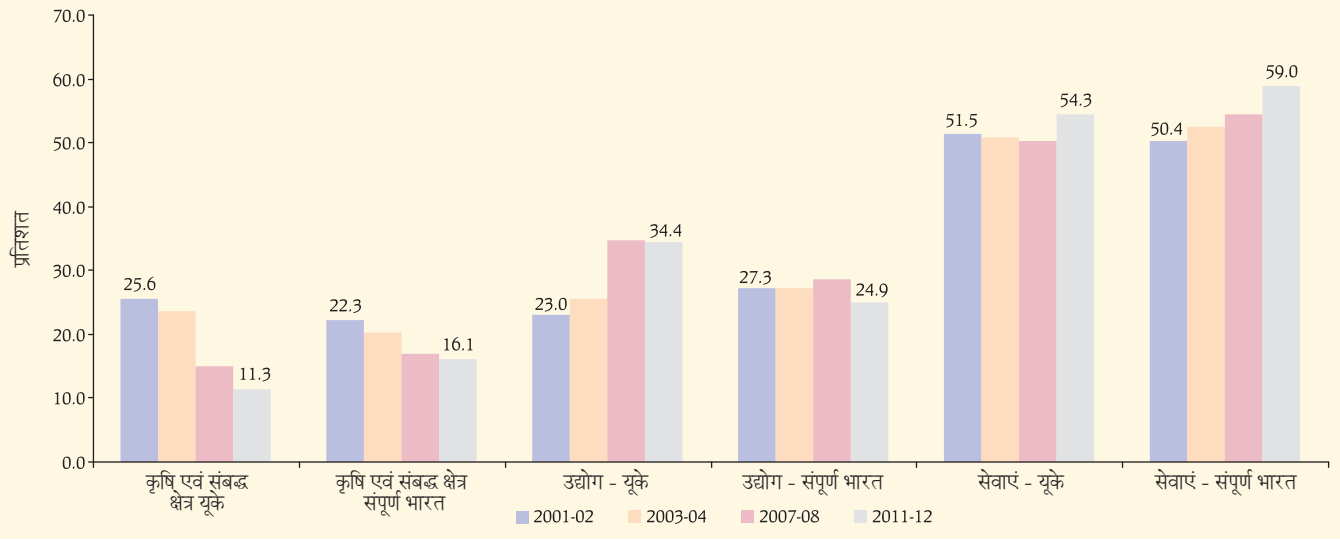

चार्ट 5 : उत्तराखंड की वृद्धि के कारक

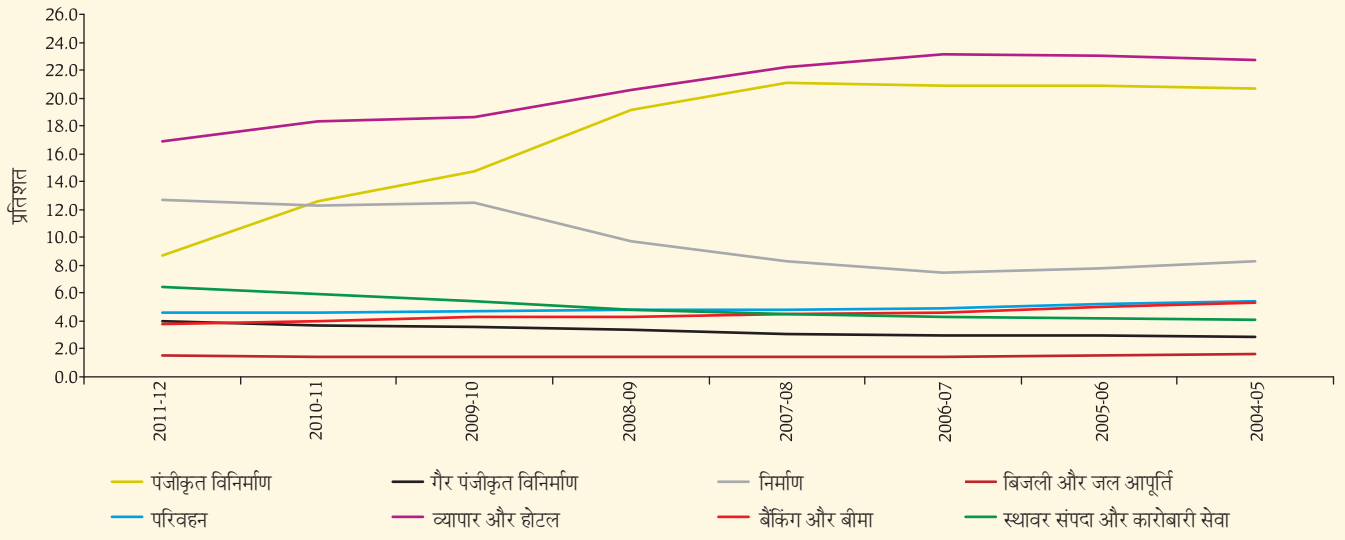

के साथ में श्रमिक शक्ति का हिस्सा 53 प्रतिशत के राष्ट्रीय स्तर की तुलना में कम रहा जिससे राज्य में बेरोजगारी का स्तर अधिक होने का पता चलता है।

सामाजिक-आर्थिक सूचक

कार्य करने में सक्षम जनसंख्या के बहुसंख्य भाग को गुणवत्तायुक्त व्यावसायिक और पेशेवर शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करके राज्य में और अधिक तेजी से वृद्धि करने की क्षमता है (चार्ट 6)।

अन्य राज्यों की तुलना में उत्तराखंड में रोजगार सृजन में अनौपचारिक क्षेत्र का हिस्सा बहुत कम है (चार्ट 7)। अतः अनौपचारिक क्षेत्र का विकास महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इससे राज्य में उपलब्ध जनसांख्यिकीय घटक का लाभ उठाने में मदद मिलेगी। अनौपचारिक क्षेत्र ऋण खपाने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

राज्य में जीवन स्तर सूचक राष्ट्रीय औसत की तुलना में बेहतर है। शुद्ध पेय जल और बिजली जैसी मूलभूत नागरी सुविधाओं की परिवारों को उपलब्धता राष्ट्रीय औसत की तुलना में अधिक है। इसी प्रकार से टेलीविजन, टेलीफोन और व्यक्तिगत मोटरगाड़ियों के यातायात साधनों जैसे घरेलू सामानों के स्वामित्व के मामले में भी

चार्ट 6 : जनसंख्या का आयु समूह वार विवरण

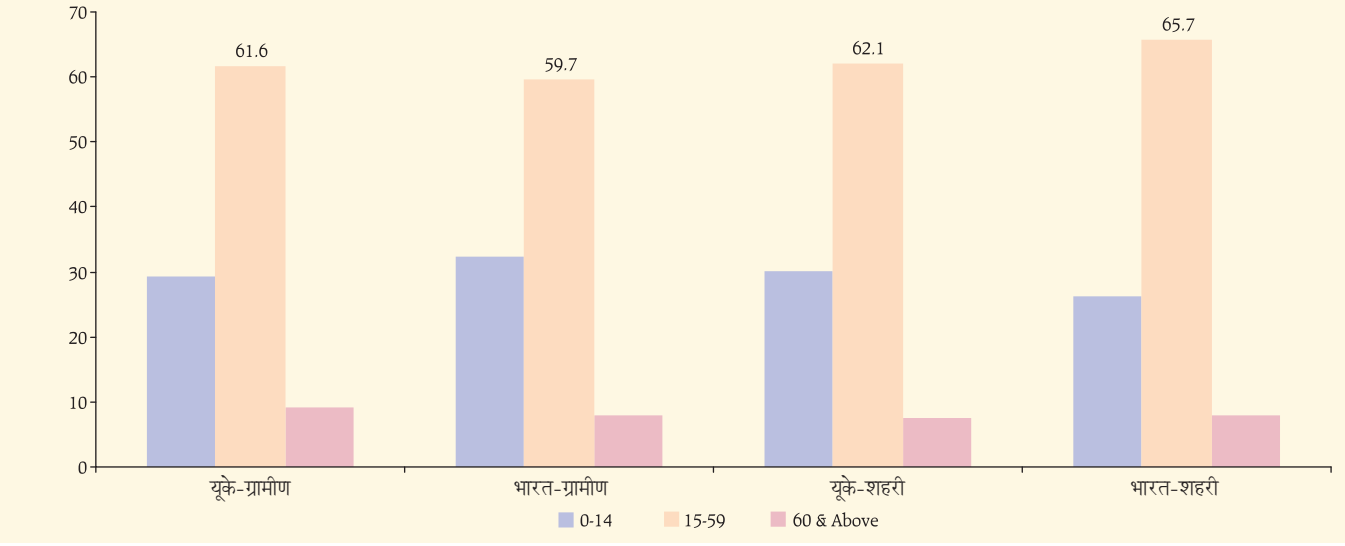

चार्ट 7 : रोजगार में अनौपचारिक क्षेत्र की भूमिका

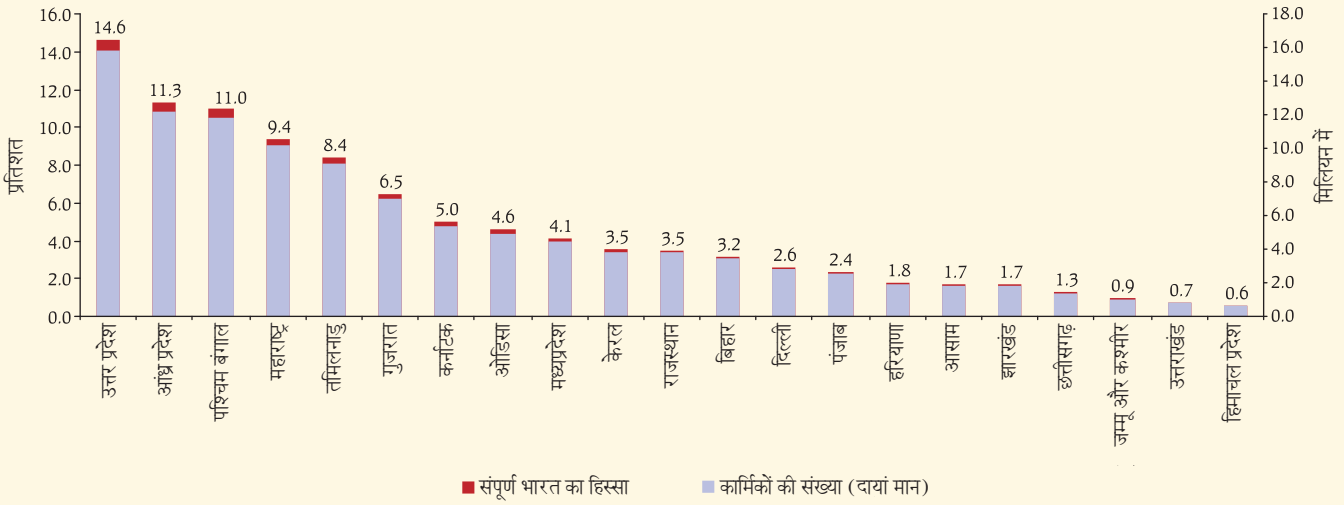

स्रोत : राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन 67वां राउंड, जुलाई 2010 से जून 2011

उत्तराखंड की स्थिति राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। लोगों को बैंकिंग सुविधा की उपलब्धता के मामले में भी उत्तराखंड की स्थिति राष्ट्रीय औसत से बढ़िया है (सारणी 2)।

आर्थिक संवृद्धि और सुविधाओं की बेहतर उपलब्धता के बाद भी विशिष्ट मानव विकास दृष्टिकोण से राज्य पिछड़ा हुआ है। उच्च साक्षरता और प्रतिव्यक्ति आय के अधिक होने के बाद भी राज्य में गरीबी अधिक है और जीवन प्रत्याशा की दर राष्ट्रीय औसत की तुलना में कम है। मानव विकास सूचकांक 2007-08 में 23 राज्यों[1] में राज्य का क्रम 14वें स्थान पर है (चार्ट 8)।

सारणी 2 : जीवन स्तर सूचक

(परिवारों के प्रतिशत के रूप में)

श्रेणी	उत्तराखंड		संपूर्ण भारत	
	2001	2011	2001	2011
	सुविधाएं			
परिसर में पेय जल	44.8	58.3	39.0	46.6
बिजली	60.3	87.0	55.9	67.3
परिसर में सीखने की सुविधा	45.2	65.8	36.4	46.9
	आस्तियां			
टेलीविजन	42.9	62.0	31.6	47.2
कंप्यूटर	-	11.0	-	9.5
टेलीफोन	9.9	74.6	9.1	63.2
दुपहिया वाहन	11.9	22.9	11.7	21.0
चार पहियों वाले वाहन	2.7	6.2	2.5	4.7
	सुविधाएं			
बैंकिंग	59.8	80.7	35.5	58.7
	हाउसहोल्ड			
हाउसहोल्ड (मिलियन में)	1.6	2.0	192.0	246.7

स्रोत : जनगणना 2011, भारत सरकार।

राजकोषीय प्रवृत्तियां

राज्य में विभिन्न राजकोषीय सुधार लागू किए गए हैं जैसे, मूल्य संवर्धित करों को लागू करना, राजकोषीय दायित्व अधिनियम पारित करना, नई पेंशन योजना की शुरुआत, प्रत्याभूतियों की अधिकतम सीमाएं तय करना, और समेकित ऋण शोधन निधि और प्रत्याभूति उद्धार निधि की स्थापना करना। नियम आधारित राजकोषीय ढांचे के तहत राज्य की राजकोषीय स्थिति में सुधार हुआ और 2006-07 में राज्य में राजस्व अधिशेष की स्थिति रही। 2006-07 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में सकल राजकोषीय घाटे का अनुपात भी 2.4 प्रतिशत घटा। हालांकि, 2009-10 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में कमी की प्रवृत्ति और व्यय में वृद्धि के कारण राजस्व खाते में घाटा हुआ। समग्ररूप से समष्टि आर्थिक स्थितियों में सुधार होने के साथ राज्य ने राजकोषीय सुधार की प्रक्रिया को प्राप्त कर लिया है। 2011-12 में राजस्व खाते में अधिशेष देखा गया किंतु अधिक पूंजीगत व्यय होने के कारण सकल राजकोषीय घाटा-राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में वृद्धि हुई है (सारणी 3)।

[1] आसाम को छोड़कर उत्तर पूर्वी राज्यों को एक इकाई माना गया इसलिए मानव विकास सूचकांक की श्रेणियों के लिए *भारतीय मानव विकास रिपोर्ट 2011, भारत सरकार* में 23 राज्यों की तुलना की गई।

चार्ट 8 : मानव विकास सूचकांक

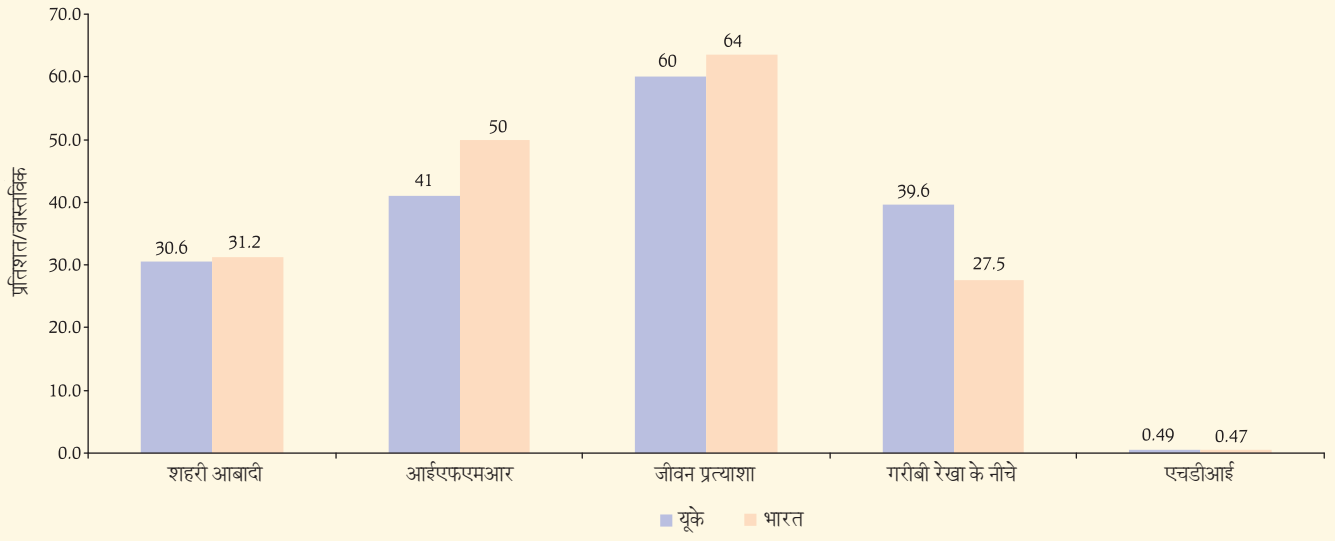

वित्तीय संकेतक

उच्च आर्थिक संवृद्धि के लिए वित्तीय गतिविधियों का स्तर बहुत महत्त्वपूर्ण होता है। भारत में औपचारिक वित्तीय प्रणाली में बैंकों का प्रभुत्व है और उत्तराखंड के मामले में भी ऐसा ही है। राज्य में प्रति बैंक शाखा के क्षेत्राधीन जनखंख्या मार्च 2012 में 7,300 थी जो अखिल भारतीय औसत 12,700 की तुलना में बेहतर है। अखिल भारत की तुलना में बैंकिंग की पहुंच अपेक्षाकृत अधिक होने के बाद भी गांवों के तितर-बितर होने की प्रकृति के कारण बैंक कवरेज बढ़ाने की काफी गुंजाइश है (चार्ट 9)।

सारणी 3 : उत्तराखंड की राजकोषीय स्थिति

(राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में)

मदें	2004-08	2008-12	2012-13
राजस्व प्राप्तियां	18.1	15.4	16.4
स्वयं के कर राजस्व	6.1	5.7	6.1
चालू अंतरण	10.3	8.8	9.1
राजस्व व्यय	18.1	15.7	16.0
विकास राजस्व व्यय	10.9	9.8	9.6
ब्याज भुगतान	2.8	2.0	2.1
पूंजीगत व्यय	0.9	2.0	3.7
सामाजिक क्षेत्र में व्यय	8.8	8.1	9.2
राजस्व घाटा	1.2	-0.3	-0.4
सकल राजकोषीय घाटा	6.3	3.2	3.4
प्राथमिक घाटा	3.4	1.1	1.4
बकाया देयताएं (अंतिम बिंदु) *	31.9	26.8	27.1

स्रोत : राज्य सरकार का बजट दस्तावेज।

दिसंबर 2011 में राज्य का ऋण-जमा अनुपात 34.2 प्रतिशत रहा जो अखिल भारतीय ऋण-जमा अनुपात के 75.7 प्रतिशत की तुलना में काफी कम है। हाल के वर्षों में राज्य के ऋण-जमा अनुपात में सुधार के संकेत दिखाई दिए हैं फिर भी यह अखिल भारतीय औसत से काफी कम है जिससे ऋण विस्तार की संभावना रेखांकित होती है (चार्ट 10)।

ऋण तीव्रता की एक अन्य माप राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में बैंक जमा का अनुपात होता है जो उत्तराखंड में अखिल भारतीय औसत की तुलना में कम है। इससे ऋण के और अधिक विस्तार की आवश्यकता होने की सूचना मिलती है (चार्ट 11)।

चार्ट 9 : बैंकिंग कवरेज

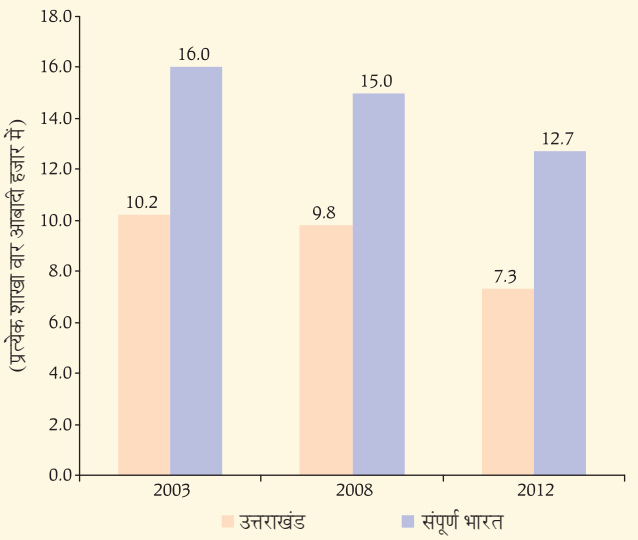

चार्ट 10 : ऋण-जमा अनुपात की प्रवृत्तियां : उत्तराखंड

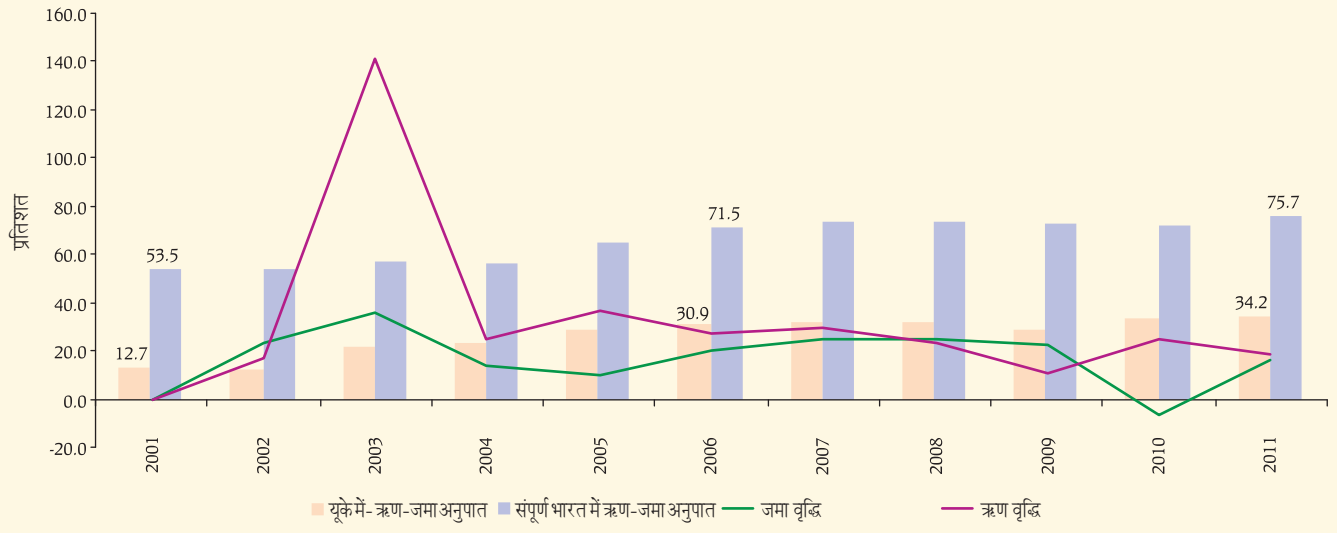

समग्ररूप से ऋण-जमा अनुपात न सिर्फ कम है बल्कि विभिन्न जिलों के बीच भी विचारणीय घटबढ़ दिखाई देती है। ऋण वितरण में विस्तृत असमताओं से राज्य के पहाड़ी इलाकों में वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाने के लिए और अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता का संकेत मिलता है।

असमग्र गतिविधि स्तर पर कृषि ऋण का हिस्सा अपेक्षाकृत कम रहा जिसमें विभिन्न जिलों के बीच विचारणीय अंतर देखा गया (चार्ट 13)। पहाड़ी जिलों में कृषि के आजीविका के प्रमुख साधन होने के कारण जिलों के मध्य ऋण का असमान वितरण समावेशी वृद्धि के लिए हितकारी नहीं है।

वित्तीय समावेशन

इस पृष्ठभूमि के साथ अब मैं भारतीय रिज़र्व बैंक की वित्तीय समावेशन की रणनीति और उत्तराखंड के लिए उठाए गए विशिष्ट कदमों की चर्चा करूंगा। समावेशी वृद्धि के लिए यह आवश्यक है कि समाज के गरीब और सुविधा से वंचित तबके को बैंकिंग के अंतर्गत लाया जाए। इस संदर्भ में, वित्तीय समावेशन के हमारे हाल के प्रयास के चार प्रमुख बिंदु हैं।

पहला, कमजोर और वित्तीय रूप से विलग तबके के लिए मूलभूत वित्तीय उत्पादों और सेवाओं का प्रावधान करना। इसके

चार्ट 11 : उत्तराखंड में ऋण का विस्तार

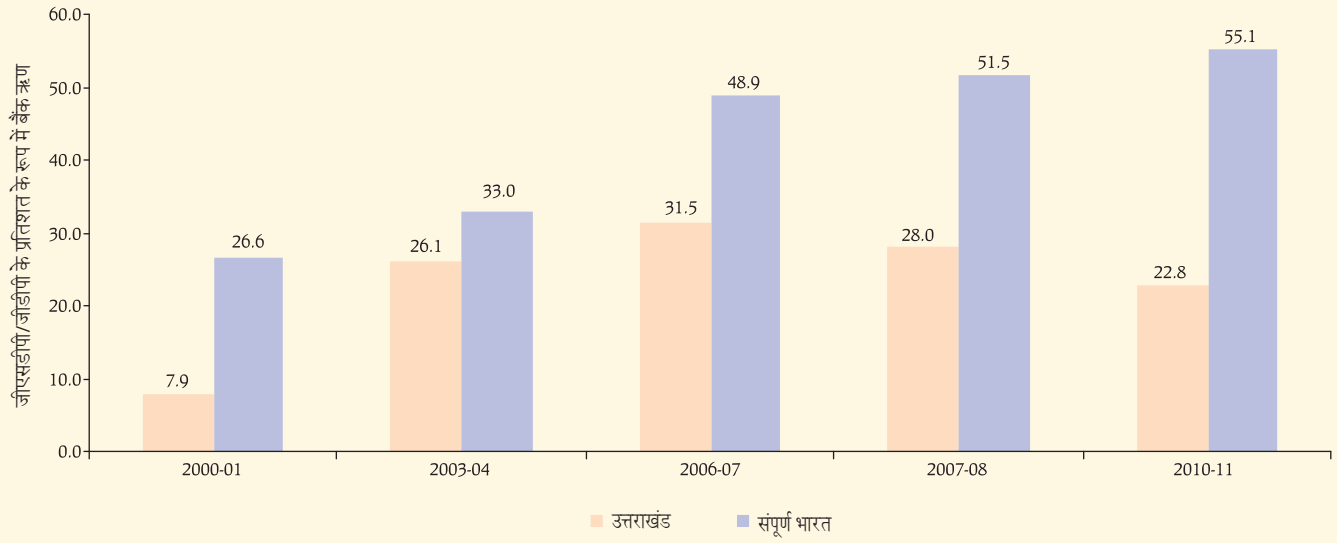

चार्ट 12 : जिला वार ऋण-जमा अनुपात का वितरण

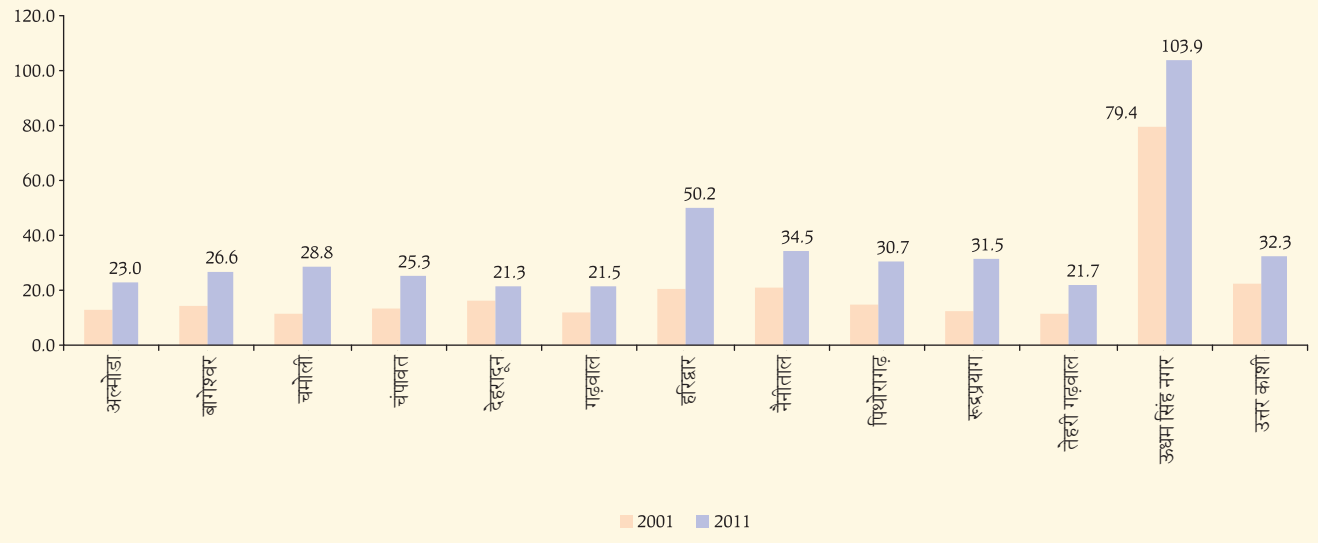

अंतर्गत नो-फ्रिल्स खाते के रूप में बचत सह ओवरड्राफ्ट उत्पाद तथा किसान क्रेडिट कार्ड/सामान्य क्रेडिट कार्ड के रूप में उद्यमिता ऋण आते हैं (सारणी 4)।

दूसरा, सभी लोगों के लिए उपलब्ध वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के बारे में समाज के सभी तबकों में जागरुकता उत्पन्न करके वित्तीय साक्षरता का प्रसार करना।

तीसरा, ब्याज दरों तथा शाखा लाइसेंसिंग को उदार बनाकर विनियामकीय प्रोत्साहनों को बढ़ाना। बैंकों को दिए जाने वाले ऋणों पर ब्याज दर निर्धारित करने की पूरी छूट दी गई है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण देना एक वाणिज्यिक प्रस्ताव बन सके। औपचारिक ऋण के न्यून विस्तार और साहूकारों से ऋण लेने के कारण ऋण की उपलब्धता अधिक महत्त्वपूर्ण है न कि उसकी लागत। 1,00,000 से कम आबादी वाले केंद्रों में शाखाएं खोलनें के लिए बैंकों को आजादी दी गई है।

चौथा, प्रौद्योगिकी और नवोन्मेषी भुगतान मॉडलों का प्रयोग करना ताकि बहुतायत में होने वाले छोटे लेनदेन की लागत को कम किया जा सके। इस प्रयास के अंतर्गत बैंकों के प्राधिकृत अभिकर्ताओं के माध्यम से वित्तीय उत्पादों और सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए बिजनेस कॉरेस्पांडेंट मॉडल को तथा केंद्र और राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजन जैसी कल्याणकारी योजनाओं

चार्ट 13 : कृषि ऋण की विभिन्न जिलों में घटबढ़

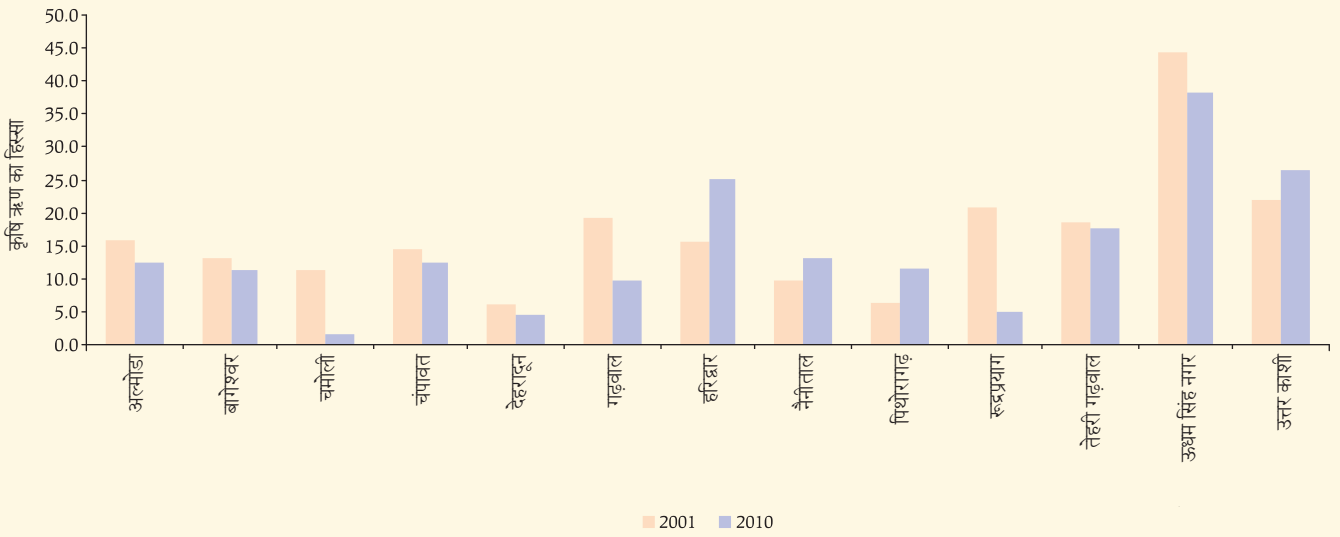

सारणी 4 : वित्तीय समावेशन योजना के अंतर्गत हुई प्रगति

	विवरण	मार्च 2010	मार्च 2011	मार्च 2012
1.	नियोजित ग्राहक सेवा केंद्रों की संख्या	33,042	57,329	95,767
2.	बैंकिंग केंद्र-गांव >2000 - उपयोग	27,353	54,246	82,300
3.	बैंकिंग केंद्र-गांव >2000 -शाखाएं	19,572	20,691	22,706
4.	बैंकिंग केंद्र-गांव >2000 -बिजनेस कॉरेस्पांडेंट	7,687	33,181	58,113
5.	बैंकिंग केंद्र-गांव >2000 -अन्य रूप	94	374	1,481
6.	बैंकिंग केंद्र-गांव >2000 - उप योग	26,905	45,937	65,234
7.	बैंकिंग केंद्र-गांव >2000 - शाखाएं	1,903	1,971	1,995
8.	बैंकिंग केंद्र-गांव >2000 - बिजनेस कॉरेस्पांडेंट	24,997	43,957	62,242
9.	बैंकिंग केंद्र-गांव >2000 -अन्य रूप	5	9	997
10.	बैंकिंग केंद्र-सभी गांव - शाखाएं	21,475	22,662	24,701
11.	बैंकिंग केंद्र-सभी गांव - बिजनेस कॉरेस्पांडेंट	32,684	77,138	120,351
12.	बैंकिंग केंद्र-सभी गांव - अन्य रूप	99	383	2,478
13.	बैंकिंग केंद्र-सभी गांव - कुल	54,258	100,183	147,534
14.	बिजनेस कॉरेस्पांडेंट के माध्यम से कवर किए गए शहरी केंद्र	433	3,757	5,875
15.	नो-फ्रिल्स खाते (संख्या मिलियन में)	49	74	103
16.	नो-फ्रिल्स खातों में राशि (राशि बिलियन ₹ में)	43	57	93
17.	अधिक निकासी वाले नो-फ्रिल्स खाते (संख्या मिलियन में)	0.1	0.6	1.5
18.	अधिक निकासी वाले नो-फ्रिल्स खातों में राशि (राशि बिलियन ₹ में)	0.1	0.2	0.6
19.	किसान क्रेडिट कार्ड (संख्या मिलियन में)	18	20	22
20.	किसान क्रेडिट कार्ड (राशि बिलियन ₹ में)	987	1,324	1,781
21.	सामान्य क्रेडिट कार्ड (संख्या मिलियन में)	0.5	1.1	1.3
22.	सामान्य क्रेडिट कार्ड (राशि बिलियन ₹ में)	6	21	25
23.	आईसीटी आधारित खाते - बिजनेस कॉरेस्पांडेंट्स के माध्यम से (संख्या मिलियन में)	13	30	52
24.	आईसीटी आधारित खाते - लेनदेन (संख्या मिलियन में)	19	64	120
25.	आईसीटी आधारित खाते -लेनदेन (राशि बिलियन ₹ में)	6	55	88

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक।

के अंतर्गत लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे राशि जमा करने के लिए इलेक्ट्रानिक बेनेफिट ट्रांसफर (ईबीटी) को अपनाया गया है।

इस दिशा में अभी तक यह प्रयास किया गया है कि 2,000 से अधिक जनसंख्या वाले सभी गांवों में मार्च 2012 के अंत तक बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाए। पिछले दो वर्षों में बैंकिंग कवरेज को बढ़ाने में सचमुच उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हमारा अगला कदम 2,000 से कम जनसंख्या वाले गांवों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना है। ऐसे गांवों में समयबद्ध ढंग से बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य स्तरीय बैंकर समितियां रूपरेखा तैयार करने में लगी हुई हैं। अर्थपूर्ण वित्तीय समावेशन के लिए इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है कि 8-10 बिजनेस कॉरेस्पांडेंटों के समूह के लिए 3-4 किलोमीटर की समुचित दूरी पर बैंक की एक भौतिक शाखा खोली जाए।

उत्तराखंड में वित्तीय समावेशन

उत्तराखंड में बैंकों ने 2,000 से अधिक जनसंख्या वाले चिह्नित 226 गांवों में मार्च 2012 के अंत तक बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किया है। इनमें से 18 गांवों में पक्की शाखाएं खोली जाएंगी तथा 198 गांवों में बिजनेस कॉरेस्पांडेंट नियुक्त करके और 10 गांवों को कियोस्क के माध्यम से बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

इसके अलावा, राज्य सरकार ने 259 छोटे गांवों के समूह को *न्यायपंचायत* के रूप में चिह्नित किया है जिनमें से 108 गांवों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराई गई है तथा शेष 151 में 2012-13 के दौरान यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। 1,000 से 2,000 के बीच जनसंख्या वाले 743 गांवों को 2012-13 में प्रोविजन बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चिह्नित किया गया है।

जून 2012 तक 8.6 लाख नो-फ्रिल्स खाते खोले गए। 2011-12 के दौरान 1.2 लाख किसान क्रेडिट कार्ड और 1200 सामान्य क्रेडिट कार्ड जारी किए गए तथा 2600 स्व सहायता समूहों का गठन किया गया। 13 में से 10 जिलों में वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श केंद्र (एफएलसीसी) हैं।

इसके अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने अधिकारियों के द्वारा आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से वित्तीय समावेशन कार्यक्रम की शुरुआत की है ताकि वित्तीय सेवाओं की वास्तविक स्थिति की जानकारी हो सके तथा वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित किया जा सके। मैं कल आउटरीच कार्यक्रम में भाग लेने के लिए नैनीताल के समीप मायारामपुर जा रहा हूं।

नीतिगत चुनौतियां

अब मैं राज्य के विकास की योजना के लिए कुछ व्यापक समष्टि आर्थिक नीतिगत चुनौतियों की चर्चा करूंगा।

पहला, कृषि में विविधता को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है जो कि कृषि-मौसमी कारकों के अनुसार होनी चाहिए। इससे क्षेत्रीय असमानता को कम किया जा सकेगा और गरीबी उन्मूलन किया जा सकेगा। कृषि के विकास को समुचित भंडारण, वेयरहाउसिंग और विपणन सुविधाओं के माध्यम से समर्थन की आवश्यकता है ताकि अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार का सृजन हो सके।

दूसरा, राज्य की विशिष्ट जैव-विविधता के अनुरूप वहनीय औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के कदम उठाने की आवश्यकता है जिससे स्थानीय रोजगार का सृजन होगा और पलायन कम होगा। राज्य में जल संसाधनों की प्रचुरता होने के कारण पर्यावरणीय दृष्टि से वहनीय ढंग से जल-विद्युत क्षेत्र को विकसित किया जाना अपेक्षाकृत आसान है।

तीसरा, राज्य में आधारभूत संरचना की कमी को निजी क्षेत्र के सहयोग से पूरा किए जाने की आवश्यकता है। बेहतर आधारभूत संरचना से पर्यटन क्षमता का दोहन करना संभव हो पाएगा। चिह्नित पर्यटन क्षेत्रों को बेहतर गुणवत्ता वाली सड़कों से जोड़ा जा सकता है साथ ही मध्यम अवधि के बाद उन्हें हवाई मार्ग से जोड़ने की संभावनाओं का भी पता लगाया जा सकता है।

चौथा, साक्षरता की दर उच्च होने से ज्ञान आधारित उद्योगों के और अधिक विकास की भी संभावना है। इसलिए ज्ञानवान-कार्मिकों की उपलब्धता के लिए गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा केंद्रों की स्थापना करने की आवश्यकता है।

पांचवां, ऋण संस्कृति को सुधारने की आवश्यकता है। इसके लिए बैंक आवश्यकतानुसार नए कारोबारी मॉडलों की खोज कर सकते हैं जिनमें समूह-ऋण पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए। ऐसा होने से ऋण के असमान वितरण में कमी लाने में सहायता मिलेगी।

छठा, राज्य के वित्तीय क्षेत्र में वाणिज्य बैंकों का प्रभुत्व है। अतः आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार महत्त्वपूर्ण है। इस संदर्भ में, नो-फ्रिल्स खातों की संख्या में हुई वृद्धि से कवरेज की मात्रा में दिखाई देने वाली उपलब्धि को अर्थपूर्ण वित्तीय समावेशन के रूप में बदलने के लिए इन खातों से सक्रिय ऋण और जमा लेनदेन को बढ़ाने की आवश्यकता है। छोटे आकार वाली बिखरी हुई बस्तियों के साथ में राज्य की भौगोलिक विशिष्टताओं के कारण बैंक की भौतिक शाखाओं की स्थापना में कठिनाईयां हैं। इसलिए सूचना प्रौद्योगिकी पर निर्भरता के साथ चलायमान शाखाओं पर जोर दिया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया में सभी सहभागियों - बैंक, राज्य सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक - को सघन समन्वय के साथ में काम करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया में बैंक यह सुनिश्चित करें कि बिजनेस कॉरेस्पांडेंट सक्रिय रहें और बैंक रहित क्षेत्रों में धीरे-धीरे शाखाओं की संख्या बढ़ाई जाए, राज्य सरकार यह सुनिश्चित करें कि सामाजिक लाभों का अंतरण उत्तरोत्तर बैंक खातों के माध्यम से किया जाए और भारतीय रिज़र्व बैंक प्रभावी पर्यवेक्षण तथा राज्य में वित्तीय समावेशन योजना का सक्रिय रूप से समन्वय सुनिश्चित करें।

निष्कर्ष

मैंने उत्तराखंड की हाल की आर्थिक और वित्तीय गतिविधियों की संक्षिप्त समीक्षा की है और समावेशी संवृद्धि के लिए कुछ सुझाव दिया है। मैं कृषि अर्थव्यवस्था पर अपने कुछ विचारों के साथ समापन करूंगा क्योंकि इस विश्वविद्यालय में कृषि क्षेत्र की प्रौद्योगिकीय खोजों का प्रारंभिक विकास हुआ है।

जैसा कि हम लोगों ने चर्चा की है, राष्ट्रीय और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के हिस्से में तेजी से कमी हुई है। हालांकि आज भी हमारी श्रम शक्ति का 52 प्रतिशत और जनसंख्या का 69 प्रतिशत भाग अपनी आजीविका के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। अतःवहनीय समावेशी संवृद्धि के लिए कृषि विकास केंद्र बिंदु है। हालांकि, कृषि में आया ठहराव वृद्धि के मार्ग में प्रमुख बाधा के रूप में प्रकट हो रहा है। यह कई रूपों में दिखाई दे रहा है जैसे सभी फसलों की पैदावार में कम और उत्पादन में अधिक उतार-चढ़ाव, खाद्य उत्पादों की प्रतिव्यक्ति कम उपलब्धता और साथ ही खाद्य मुद्रास्फीति का लगातार उच्च स्तर पर बने रहना।

विस्तृत रूप से वैश्विक स्तर पर प्राकृतिक आपदाओं के अधिक बार आगमन से भी भू-मौसमी परिस्थितियों में भी परिवर्तन आया है। चूंकि देश में उपलब्ध कृषि योग्य 142 मिलियन हेक्टेयर के

क्षेत्रफल में वृद्धि होने की संभावना नहीं है, इसलिए खाद्य उत्पादन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उत्पादकता को बढ़ाना होगा। इस संबंध में, कम-अवधि वाले सूखा-सह उच्च उत्पादन वाले न सिर्फ अनाज बल्कि दालों और तिलहन को विकसित करने के लिए प्रौद्योगिकीय खोजों के दौर की आवश्यकता है। देश में भू-स्वामित्व के छोटे आकार के पैटर्न को देखते हुए छोटे जोत आकार के लिए उचित प्रौद्योगिकी का विकास करना भी महत्त्वपूर्ण है। उद्यानिकी, कुक्कुट पालन, डेयरी और मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी विकास की आवश्यकता है, जिनका भविष्य में उपभोग बढ़ने वाला है। एक और हरित क्रांति लाने में, जिसके लिए इस विश्वविद्यालय को पहले ही गौरव प्राप्त है, के इस यत्न में आप जैसे कृषि वैज्ञानिकों और नेताओं की भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण होगी।